

during the 8th Plan is 30531 MW, with the following break-up:—

	(MW)
Central Sector (inclusive of Nuclear Power Corporation & Neyveli Lignite Corporation (NLC))	12858
State Sector (inclusive of 2810 MW in private sector)	17680
	30538

The above capacity benefits are exclusive of the additional capacity benefits likely to accrue during the 8th Plan from new private sector projects that are likely to be set up. Presently, 24 proposals (14082.50 MW) for setting up power projects in the country in the private sector at a total estimated cost of Rs. 35322.82 crores are under consideration of the Central Government.

The total public sector 8th Plan outlay for Power is Rs. 79589.32 crores, as indicated in the 8th Plan document approved by the National Development Council. The break-up is as follows:

	(Rs. crores)
Centre (inclusive of NDC & NLC)	31181.58
States	48407.74

Per capita consumption of electricity

2860. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of POWER be pleased to state;

(a) what is the annual per capita consumption of electricity both in the rural and urban areas;

(b) how does it compare with the per capita consumption of electricity in the developed countries;

(c) whether with the development of the economic sectors in the country there is an overall shortfall in the supply of electricity to the industrial, agricultural, commercial sectors and also for

domestic consumption, if so, the details thereof; and

(d) what is the strategy formulated by Government to augment the generating capacity both hydle, thermal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) The annual per capita consumption of electricity in the country, urban and rural sectors taken together, was 253.41 Kwh. (Provisional) during the year 1990-91 which is low as compared to the same in the developed countries.

(c) During the year 1991-92, the all-India energy shortfall, to various categories of consumers, was 7.8 per cent.

(d) It is proposed to add a capacity of 30538 MW comprising of 9282 MW hydro, 20156 MW thermal and 1100 MW nuclear in the 8th Five Year Plan,

IP Thermal Power Station, Delhi

2861. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of POWER be pleased to state;

(a) whether it is a fact that of the six gas turbine units of I.P. Thermal Power Station, Delhi, two have been nonfunctional for the last two years;

(b) if so, what-are the- reasons for delay in making them functional;

(c) whether it is also a fact that the turbines commissioned by a French Firm some six years back have been constantly giving trouble and DESU lacks technical expertise to run and maintain the Plant;

(d) if so, what are the considerations for going in for French technology when DESU lacked in technological know-how to run and maintain the plant; and

(e) what measures have been taken by Government to ensure Its normal functioning?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP-NATH RAI): (a) to (e) At present out of six Gas Turbines of DESU, only one unit is non-functional. DESU has the technical expertise and is not facing any

major problem in running and maintaining the Gas Turbines. Scheduled maintenance of the Gas Turbines is carried out from time to time and adequate stocks of spare parts are also maintained to ensure proper functioning of the Units.

राजस्थान की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

2862. श्री शिवचरण सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि

(क) राजस्थान की कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएँ केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी तथा इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान में विद्युत उत्पादन और खपत में भारी अन्तर है ; यदि हाँ, तो इस अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ये कदम कब तक उठाये जायेंगे ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथराय) : (क) और (ख) मैसर्स सैन्चुरी टैक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में निजी क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत केन्द्र (1×500 मे०वा०) की स्थापना के संबंध में परियोजना रिपोर्ट फरवरी, 1992 में तकनीकी - आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी। कायल लिकेज, पर्यावरण एवं दान संबंधी स्वीकृति आदि जैसे कुछ निवेशों को के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु अपेक्षित है, जो अभी सुनिश्चित किया जाना है। धोलपुर ताप विद्युत केन्द्र (3×250×750 मे०वा०) की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को प्रारंभ में अप्रैल, 1987 में पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था और अन्य कार्यस्थल के संबंध में संशोधित स्कीम प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया था। के० वि० प्रा० में मई, 1991 में प्राप्त संशोधित प्रस्ताव की तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) राजस्थान को ऊर्जा की मामूली कमी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 1991-92, जून 1992 तथा अप्रैल-जून, 1992 की अवधि के दौरान राजस्थान में वास्तविक विद्युत सप्लाई स्थिति नीचे दी गई है :—

(सभी आंकड़े निचले मि०यू० में)

	1991-92	जून, 1992	अप्रैल-जून 1992
आवश्यकता	13220	1110	3485
उपलब्धता	13830	1056	3311
कमी %	190(1.4)	54(4.9)	94(2.8)

राज्य में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए उत्तरी क्षेत्र ; स्थित केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से नियत आउटपुट के अलावा राजस्थान को उत्तरी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत

केन्द्रों के 15% अनाबंटित में से भी उक्त क्षेत्रों के संघटकों में विद्युत की सापेक्ष प्रतिशत कमी को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है।